कृषि कुंभ (अगस्त, 2023),
खण्ड 03 भाग 03, पृष्ठ संख्या 95–97

जीरो हंगर लक्ष्य – चुनौतियाँ एवं भारत के प्रयास

हेमराज मीना[1], धर्मेंद्र कुमार[2] एवं हीरा लाल शर्मा[3]
[1]सहायक प्राध्यापक, कृषि विभाग
माता गुजरी कॉलेज, फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)
[2,3]सहायक प्राध्यापक, कृषि विभाग
संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा (राजस्थान), भारत।
Email Id: hemumeena92@gmail.com

भूख को समझना मुश्किल है। इसके कई अर्थ हैं– खाना खाने की इच्छा न करना, दो टाइम का खाना न खाना, प्रतिदिन की तय कैलोरी न लेना और खाद्य असुरक्षा की व्यक्तिपरक भावना। दुनिया भर में मौत का मुख्य कारण भूख है। हमारे ग्रह द्वारा हमें दिए गए प्रचुर संसाधनों के बावजूद, असमान पहुंच और अप्रभावी प्रबंधन के कारण लाखों लोग अल्पपोषित हैं।

2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 116 देशों की सूची में 101 वें पायदान पर है और भुखमरी की गंभीर श्रेणी के तहत यह आता है। भारत में भुखमरी की तीव्रता 27.9 प्रतिशत है तो यहां 45.9 प्रतिशत बहुआयामी गरीबी की स्थिति है, जिसमें नागरिकों को बड़ी संख्या में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जीवन स्तर में कमी का सामना करना पड़ रहा है, कुपोषण की समस्या दशकों से भारत को जकड़े हुए है और गरीबी और आर्थिक पतन की यह प्राथमिक वजह है। यदि हम समकालीन प्रौद्योगिकियों और समान वितरण तंत्रों का उपयोग करके टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करते हैं तो हम पूरी दुनिया की आबादी का समर्थन कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी को भी फिर कभी भूख का अनुभव नहीं करना पड़े।

चुनौतियाँ

- खाद्य प्रणाली के सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किये गए प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों में से एक जलवायु परिवर्तन में इसका योगदान है।
- खाद्य प्रणाली मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 34 प्रतिशत का योगदान करती है।
- जल संसाधनों का अत्यधिक उपभोग कृषि के सामने एक और महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
- सिंचाई वैश्विक जल निकासी के लगभग 70 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है और आने वाले दशकों में इस मांग में वृद्धि की उम्मीद है।
- नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का अत्यधिक उपयोग स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिये हानिकारक है।
- मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता तथा मीठे पानी के अम्लीकरण का कारण बनती है और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन एवं समतापमंडलीय ओजोन परत में छेद का कारण बनती है।
- दुनिया भर में विभिन्न राहत उपायों के बावजूद संकट के दौरान कई बहुआयामी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। वैश्विक स्तर पर 2 अरब से अधिक लोगों के पास अभी भी पर्याप्त पौष्टिक और सुरक्षित

भोजन तक पहुँच सुनिश्चित नहीं हो सकी है।

- अनुमानों के अनुसार दुनिया में वर्ष 2030 तक जीरो हंगर या वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर नहीं है।
- जलवायु परिवर्तन कृषि विविधता के लिये एक वास्तविक और प्रबल खतरा बना हुआ है, जो उत्पादकता से लेकर आजीविका और खाद्य प्रणालियों को भी प्रभावित करेगा।
- वर्तमान में कीटों और टिड्डियों के आक्रमण तथा चक्रवात की घटनाएँ किसानों के समक्ष निरंतर चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं, जिनका खाद्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।
- रसायनों के अत्यधिक प्रयोग तथा असंगत कृषि पद्धतियों के कारण भू–क्षरण, भूजल स्तर में तेजी से कमी तथा कृषि योग्य भूमि में भी निरंतर कमी आ रही है।
- भारत में 86 प्रतिशत से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, जो कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है।
- भारत में पिछले एक दशक में कुपोषण के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। हालाँकि व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (CNNS) 2016–18 के अनुसार भारत में 40 मिलियन से अधिक बच्चे कुपोषित हैं तथा 15–49 वर्ष की आयु की 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ रक्ताल्पता (एनीमिया) की शिकार हैं।

सुझाव

- सतत् कृषि के लिये नए निवेश, अनुसंधान और नवाचार को सुगम बनाना।
- खाद्यान्न के नुकसान को कम करना।

Source- https://www.downtoearth.org.in

- प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम करके और स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देकर "सतत विकास लक्ष्यों" (SDG) परिणामों का अधिक लाभ उठाने के लिये हमारे उपभोग पैटर्न को बदलना।
- वर्तमान में आवश्यकता है कि खाद्य फसलों के उत्पादन प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन करते हुए भोजन की बर्बादी को व्यावहारिक प्रयासों के माध्यम से रोका जाए। दुनिया में उत्पादित भोजन का लगभग एक–तिहाई हिस्सा बर्बाद हो जाता है।
- सयुंक्त राष्ट्र की तीनों एजेंसियॉः "खाद्य और कृषि संगठन" (FAO), 'कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष' (IFAD) और 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' (WFP) को धारणीय खाद्य प्रणाली (Sustainable Food System) के निर्माण के लिये सरकार, सिविल सोसाइटी और किसानों के साथ कार्य करने हेतु और अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
- हमें वर्तमान संकट के लिए एक एकीकृत प्रतिक्रिया तैयार करनी चाहिए और उन तरीकों से आगे बढ़ना चाहिए, जो वर्तमान खाद्य प्रणाली को अधिक समावेशी, टिकाऊ और लचीला बनाने में मदद करते है।

भारत के प्रयास

- पछले कुछ दशकों में भारत की कृषि उत्पादकता में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान में भारत खाद्यान्न आयातक की बजाय एक महत्त्वपूर्ण निर्यातक की भूमिका अदा कर रहा है। महामारी के समय में केंद्र और राज्य सरकारें घरेलू खाद्यान्न भंडारों से लगभग 23 मिलियन टन की खाद्य सामग्री वितरित करने में सक्षम रहीं, जिससे देशभर के जरूरतमंद परिवारों को संकट की स्थिति में सहायता प्राप्त हुई।
- भारत का ZERO HUNGER PROGRAM 16 अक्टूबर, 2017 को शुरू किया गया था। यह दिन 'विश्व खाद्य दिवस' का प्रतीक है। पहल का मुख्य उदेश्य कृषि, स्वास्थ्य और पोषण है।
- सरकार ने COVID-19 के दौरान 820 मिलियन लोगों के लिये सफलतापूर्वक राशन का प्रबंध किया। इसमें 90 मिलियन स्कूली बच्चों को भोजन प्रदान करने के वैकल्पिक उपायों को भी शामिल किया गया है।
- लॉकडाउन के दौरान आवाजाही पर प्रतिबंध के दौरान भी सरकार द्वारा सुरक्षा मानकों के तहत खाद्य आपूर्ति शृंखला की बाधाओं को दूर करने और कृषि गतिविधियों को जारी रखने हेतु सराहनीय प्रयास किये गए।
- समेकित बाल विकास सेवा पहल के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के 100 मिलियन बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पका हुआ भोजन तथा घर–घर राशन की सुविधा प्रदान की जाती है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पोषण और भुखमरी को समाप्त करने की दिशा में एक आदर्श उदाहरण है।
- भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु नवाचारी प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे सूखा और बाढ़ रोधी बीज की किस्मों का विकास, किसानों को मौसम आधारित कृषि परामर्श तथा जल की कम आवश्यकता वाली फसलों को प्रोत्साहन (बाजरे की खेती आदि) प्रदान करना।

निष्कर्ष

वर्तमान संकट खाद्य प्रणालियों में वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर नवाचारी समाधानों को लचीला और टिकाऊ बनाने का महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। अतः सरकारों, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी को एकजुटता के साथ कार्य करना होगा ताकि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वहनीय और पोषणयुक्त आहार प्राप्त हो सके।

2030 तक, हमें भुखमरी को खत्म करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी को पूरे वर्ष पर्याप्त भोजन मिले, जिसमें वंचितों और शिशुओं जैसे कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

हमें लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना चाहिए जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा दें, पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण का समर्थन करें, जलवायु परिवर्तन, मौसम में उतार चढ़ाव, जल तनाव, बाढ़ और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें और वर्ष 2030 तक धीरे–धीरे भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करें। इससे हम टिकाऊ खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित कर सकते हैं।